जीविका

JEEViKA

बिहार सरकार

THE ChangeMakers

July to September 2022 Issue 15

Transforming Rural Bihar

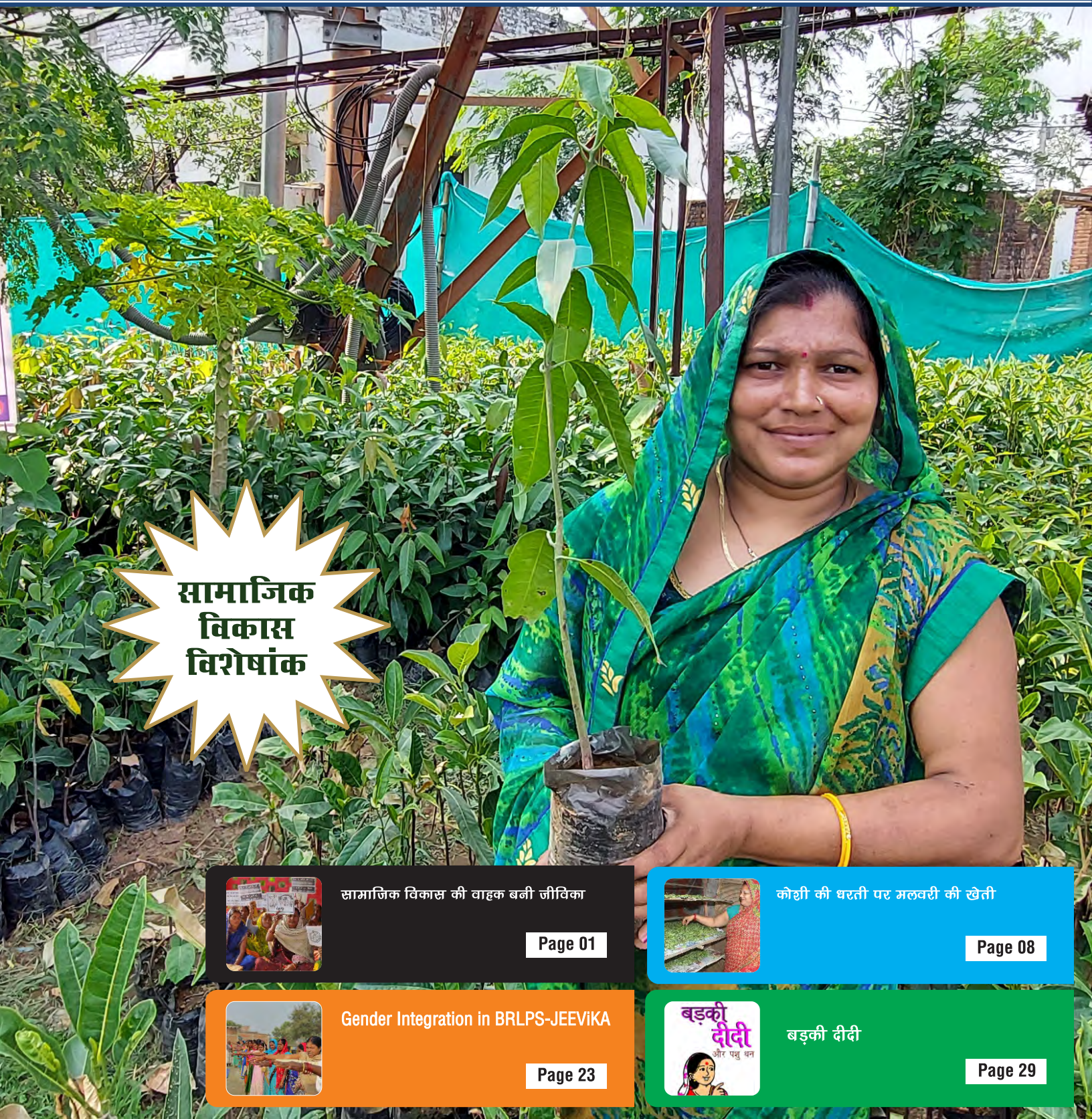

सामाजिक विकास विशेषांक

सामाजिक विकास की वाहक बनी जीविका Page 01

कोशी की धरती पर मलवरी की खेती Page 08

Gender Integration in BRLPS-JEEViKA Page 23

बड़की दीदी Page 29

From the editor's desk

Dear Readers,

Greetings.

As we celebrate 15 years of our journey in the development sphere of Rural Bihar, we bring forth the 15th edition of our "Changemakers". In this edition we present our initiatives in the social development arena of our efforts in transforming rural Bihar.JEEViKA envisages to target structural determinants by extensive Social Behaviour Change Communication Practices and intervenes in the following areas of socio-economic empowerment, like

- access to education, skills development and training,
- access to assets and financial services, collective action and leadership, adequate social protection, agency, and equitable social norms.
- contextually relevant strategies – for poorer, marginalised women

The Lead Story explains the various strategies and policies adopted to include the most vulnerable communities to accrue the benefits of collective actions. This edition further captures the initiatives taken for ensuring food security, better access to financial services, rights and entitlements and welfare programs. "Badki Didi" imparts information regarding various social protection schemes and programs. The "Didi ki Kahani Didi ki Zubani" segment has some life churning stories of JEEViKA Didis.

Thus, taking you through experiences of our endeavours, we solicit your continued support and suggestions.

Happy Reading

Regards

Mahua Roy Choudhury
pc.gkm@brlps.in

EDITORIAL TEAM

- **Mrs. Mahua Roy Choudhury**
  Program Coordinator (G&KM)
- **Mr. Ajit Ranjan**
  State Project Manager (M&E)
- **Mr. Puspendra Singh Tiwari**
  State Project Manager (BL)
- **Mr. Pawan Kr. Priyadarshi**
  Project Manager (Communication)

CONTENT COMPILATION TEAM

- **Mr. Biplab Sarkar**
  Manager Communication, SPMU
- **Mr. Rajeev Ranjan**
  Manager Communication, Samastipur
- **Mr. Bikash Kumar Rao**
  Manager Communication, Supaul
- **Mr. Manish Kumar**
  Manager Communication, Vaishali

संदेश

श्री राहुल कुमार (भा.प्र.से.)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका (BRLPS)

सह राज्य मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान सह आयुक्त मनरेगा

स्थायित्वपूर्ण विकास हमेशा सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। बिहार में जीविका द्वारा सामाजिक–आर्थिक विकास के सपने को साकार किया गया है। आज बिहार सतत् एवं स्थायित्वपूर्ण विकास के नए मानक स्थापित कर रहा है। जीविका ने सामाजिक जड़ता को तोड़ते हुए सामाजिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य किया है। पूर्ण मद्य निषेध की नीति, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के उन्मूलन के साथ–साथ महिलाओं के उत्थान एवं उनके अधिकार के लिए किए गए प्रयासों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। जल–जीवन–हरियाली अभियान, सतत् जीविकोपार्जन योजना, मनरेगा के साथ जुड़ाव जैसी गतिविधियों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक दोनों पक्षों को मजबूत करने का कार्य किया गया है। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम हमारे सामने है। जीविका दीदियां राज्य में बदलाव की नई कहानियां रच रही हैं। आज सामाजिक विकास से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों में जीविका दीदियां बढ़–चढ़ कर भाग ले रही हैं और यही कारण है कि बिहार स्थायित्वपूर्ण विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। आज जीविका के प्रयासों का परिणाम है कि बिहार की एक बड़ी आबादी सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर सशक्त हो रही हैं।

CONTENTS

सामाजिक विकास की वाहक बनी जीविका..... 01
Transforming lives of Ultra-poor Households..... 04
जीवन के लिए हरियाली जरूरी..... 06
कोशी की धरती पर मलबरी की खेती..... 08
Partnership with I-Saksham, Pratham Initiatives and Turn The Bus..... 10
जागरूकता एवं स्वावलंबन से महिलाओं ने की बराबरी..... 13

संदेश

श्री बालामुरूगन डी. (भा.प्र.से.)
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

राज्य के सामाजिक सुधार में जीविका की महत्वपूर्ण भागीदारी है। जीविका के प्रयासों का नतीजा है कि राज्य की महिलाओं के जीवन में एक नया विहान आया है। जीविका भारत की सबसे बड़ी महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण का कार्यक्रम है, जो ग्रामीण बिहार में 1 करोड़ 27 लाख से अधिक परिवारों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर कार्य कर रहे है। राज्य में समाज सुधार के प्रयासों को जीविका ने हमेशा से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। पूर्ण शराबबंदी हो, दहेज एवं बाल विवाह के उन्मूलन की बात हो या फिर स्वच्छता, जल जीवन हरियाली जैसे अभियानों को सरजमीं पर उतारने की बात जीविका दीदियों ने हमेशा से उसे पूर्णतः लक्ष्य तक पहुंचाया है। सामाजिक विकास की छोटी–छोटी कई जैसे बानगी दीदियों के हस्ताक्षर करने से लेकर उनकी व्यक्तिगत पहचान तक परिलक्षित हो रही है। कई अभिनव प्रयासों द्वारा जीविका ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहण किया है। समेकित प्रयासों का नतीजा है कि आज बिहार सामाजिक बदलाव के नए मानक स्थापित कर रहा है।

01 सामाजिक विकास की वाहक बनी जीविका

06 जीवन के लिए हरियाली जरूरी

19 मनरेगा ने जीविका दीदियों को दी नई उड़ान

23 Gender Integration in BRLPS-JEEViKA

CONTENTS

Social Development Initiatives During Covid-19..... 15
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जीविका दीदियां कर रहीं पौधशाला का निर्माण.... 17
मनरेगा ने जीविका दीदियों को दी नई उड़ान..... 19
Didi Adhikar Kendra..... 21
Gender Integration in BRLPS-JEEViKA..... 23
दीदी की कहानी : दीदी की जुबानी..... 25
बड़की दीदी 29

सामाजिक विकास की वाहक बनी जीविका

राजीव रंजन एवं विकास कुमार राव, प्रबंधक - संचार, समस्तीपुर एवं सुपौल

बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2007 में शुरू की गई जीविका परियोजना अब राज्य में सामाजिक विकास एवं बदलाव की वाहक बन गई है। बिहार में जीविका द्वारा गठित 10 लाख 35 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से करीब 1.27 करोड़ महिलाएं जुड़कर संगठित, संयमित, शिक्षित, सजग, स्वाबलंबी और सशक्त बन रही हैं। सामुदायिक संगठनों से जुड़कर महिलाओं में काफी सकारात्मक बदलाव आया है और उन्होंने विकास के पथ पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं महिलाओं की जागरूकता, सक्रियता और सामूहिकता ने समाज को भी एक नई दिशा दी है। परिवार तथा समाज में महिलाओं का मान–सम्मान बढ़ने के साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर भी दीदियां निर्णायक भूमिका निभाने लगी हैं। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रति दीदियां जागरूक हुई हैं और सही तरीके से इन योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हुई हैं। इतना ही नहीं समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराब जैसी कुरीतियों को दूर भगाने के लिए अभियान चलाकर समाज सुधार का संदेश दे रही हैं।

बहरहाल सामुदायिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक विकास के क्षेत्र में जीविका द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक विकास के तहत संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों का विवरण निम्न है–

अपने नाम से पहचान, मिला आत्मसम्मान: शुरुआत में महिलाएं जब स्वयं सहायता समूह से जुड़ रही थीं, तब उनके समक्ष पहचान का संकट था। रूढ़ीवादी परम्परा के तहत अधिकांश महिलाएं अपने पति, बेटे या मायके के नाम से जानी जाती थीं। लेकिन जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के साथ ही महिलाओं को उसके नाम से पुकारा जाने लगा। समूह की साप्ताहिक बैठकों में वे अपने नाम के साथ अपना परिचय देती हैं। इससे उन्हें अपने नाम से पहचान मिली है। जीविका की वजह से यह एक बड़ा सामाजिक बदलाव है। इसी तरह समूह से जुड़ने वाली निरक्षर महिलाओं को साक्षर करते हुए उन्हें अपना हस्ताक्षर करना सिखाया गया है। इन कदमों से उनके अंदर आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ है।

भेदभाव खत्म, आई सामाजिक समानता: जीविका ने समूह के माध्यम से समाज के सभी वर्ग, जाति एवं धर्म के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर उनमें समानता का बोध कराया है। किसी भी समूह में सभी जाति, धर्म और वर्ग की महिलाएं जुड़ी होती हैं। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ की बैठकों में सभी दीदियां बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठती हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपस में चर्चा करती हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेती हैं। इसी तरह लैंगिक भेदभाव एवं सामाजिक दूरियों को खत्म

करने के लिए जीविका द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें जागरूक किया जाता है। इस तरह महिलाओं में समानता एवं एकजुटता की भावना विकसित हुई है।

शिक्षण–प्रशिक्षण एवं संचार से महिलाओं में सजगता: समूह से जुड़ी महिलाओं को सर्वप्रथम हस्ताक्षर करना सिखाया गया, जो कि साक्षरता का पहला पैमाना है। इसके बाद समूह की बैठकों में दीदियों को समूह की कार्यप्रणाली, वित्तीय लेनदेन, बैंकिंग प्रणाली, जीविकोपार्जन गतिविधियों आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। परिणामस्वरूप महिलाएं नियमित रूप से वित्तीय लेनदेन और उसका लेखांकन करती हैं। प्रशिक्षण की वजह से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिससे वे सफलतापूर्वक अपनी आजीविकाओं का संचालन कर रही हैं। साथ ही जागरूकता एवं प्रशिक्षण की वजह से वे बैंकिंग प्रणाली से सुगमतापूर्वक जुड़ रही हैं। समूह की बैठक में उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण का ज्ञान दिया जाता है, इससे महिलाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता आई है। इसी तरह समूह की बैठकों में उन्हें विभिन्न समाजिक मुद्दों के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे वे जागरूक हुई हैं और सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में स्वयं पहल करने के लिए प्रोत्साहित हुई हैं।

समाज सुधार अभियान: शराब जैसी सामाजिक बुराई की भुक्तभोगी रही महिलाओं ने समूह एवं ग्राम संगठन के माध्यम से एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाया। परिणामस्वरूप जीविका दीदियों की मुहिम की वजह से ही बिहार में आज शराबबंदी लागू है। अब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जीविका दीदियां सजग प्रहरी की भूमिका निभा रही हैं और समाज में निरंतर जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसी तरह बाल–विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के उन्मूलन हेतु भी जीविका दीदियां सामुदायिक संगठनों के माध्यम से समाज को जागरूक कर रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण हेतु जल–जीवन–हरियाली अभियान: जीविका द्वारा सामाजिक विकास की पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण जैसा महत्त्वपूर्ण काम भी किया जा रहा है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत 'एक दीदी–एक पौधा' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक जीविका दीदियों को कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दीदियों को पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें पिको प्रोजेक्टर से वीडियो दिखाकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में बताया जाता है और रैली के माध्यम से जागरूक किया जाता है। वर्ष 2020 में मिशन 1 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। वहीं वर्ष 2021 में 1.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पिछले वर्ष जीविका दीदियों द्वारा लक्ष्य से भी अधिक पौधारोपण किया गया था। वर्ष 2022 में भी जून महीने से जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। इसके तहत आम, अमरूद, नींबू,

कटहल, जामुन, आंवला जैसे फलदार वृक्ष के अलावा इमारती लकड़ियों के पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ भविष्य में यह इन परिवारों के लिए आय प्राप्ति का भी साधन बनेगा।

दीदी की नर्सरी: जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत करोड़ों की संख्या में शिशु पौधों की मांग को देखते हुए इसकी आपूर्ति हेतु जीविका समूह से जुड़े परिवारों को नर्सरी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में मनरेगा और वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दीदी की नर्सरी हेतु कुछ जीविका दीदियों का चयन किया गया। परिणामस्वरूप आज बड़ी संख्या में जीविका दीदियों द्वारा अपनी 'दीदी की नर्सरी' में करोड़ों शिशु पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर पौधारोपण करना संभव हो पाया।

सरकारी योजनाओं से जुड़ाव: मनरेगा, राशन, पेंशन, बीमा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समूह की बैठकों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही इन योजनाओं का लाभ लेने में मदद पहुंचाई जाती है। समूह से जुड़े परिवारों को मनरेगा से जॉब कार्ड उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने तथा योजना का लाभ लेने में मदद पहुंचाई जा रही है। इसी तरह, राशन पाने से वंचित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध

कराने हेतु जीविका द्वारा जून 2020 में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें समाज के सभी छूटे हुए परिवारों के लिए राशन कार्ड बनवाया गया। इसके अलावा समूह से जुड़ी योग्य महिलाओं को वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन का लाभ दिलाने की पहल की जा रही है। वहीं आयुष्मान योजना के तहत समूह से जुड़े परिवारों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने में मदद पहुंचाई जाती है। इसी तरह समूह से जुड़े सभी सदस्यों को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उपरोक्त पहल से समूह की दीदियां सीधे लाभान्वित हो रही हैं।

सरकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण: सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण अवयव के तहत जीविका दीदियों द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इससे एक तरफ जहां जीविका दीदियों को रोजगार मिला है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराने में मदद मिल रही है।

खाद्यान्न सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु निधि: जीविका परियोजना के द्वारा ग्राम संगठनों को एक–एक लाख रुपये खाद्यान्न सुरक्षा निधि और 50–50 हजार रुपये स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के तहत राशि उपलब्ध कराई जाती है। खाद्यान्न सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य समूह से जुड़े परिवारों के लिए खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना है। इसी तरह स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का उद्देश्य समूह सदस्यों को बीमारी के समय इलाज हेतु समय पर, असानी से एवं कम दर पर पैसे की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस निधि से बड़ी संख्या में जीविका दीदियों को बीमारी के दौरान इलाज करवाने में मदद मिली।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहारा: जीविका द्वारा दिव्यांग जनों के लिए अलग से समूह का गठन कर उन्हें सम्पोषित किया जाता है। इन समूहों को विशेष पूंजीकरण निधि उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका गतिविधि से जोड़ने के साथ ही सरकार की योजनाओं का भी लाभ दिलाया जाता है।

मलबरी रेशम का उत्पादन: जीविका में सामाजिक विकास के तहत वैकल्पिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अन्य विभागों के साथ अभिसरण कर कई गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसमें से एक है–मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना। बिहार से कोशी एवं सीमांचल के सात जिलों– सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया, किशनगंज और कटिहार में संचालित इस योजना के तहत मलबरी रेशम का उत्पादन एवं रेशमी वस्त्रों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

जीविका द्वारा सामाजिक विकास के प्रयासों के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत ग्राम सगठनों को जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस दिलावाने की पहल की जाती है। इससे समुदाय आधारित संगठनों द्वारा जन वितरण का कार्य हस्तांतरित करने में मदद मिल रही है। समूह सदस्यों के बीच ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'प्रथम', 'टर्न द बस' एवं 'आई सक्षम' जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन क्षेत्र में भी जीविका द्वारा किए जा रहे प्रयास के तहत समूह से जुड़े परिवारों को बाढ़, अगलगी जैसी आपदा से बचाव हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर उन्हें जागरूक किया जाता है।

Transforming lives of Ultra-poor Households

(Focus on Disabled Group)

Shravani, YP-KMC

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS) has started various interventions under the Social Development in Bihar. The main objective of social development interventions is to achieve the social inclusion of the marginalized and poorest households in Bihar. The vicious link between poverty and disability lead to the social exclusion of persons with disabilities in the state. In order to address the issue, the Jeevika has come up with a road map for the inclusive development of persons with disabilities as part of its poverty alleviation program.

Since 2015, Jeevika has been working with persons with disabilities through its interventions under Social Development. On 20th December, 2016 Jeevika has signed an MOU with the Sightsavers (Royal Commonwealth Society for the Blind). According to the MOU, Sightsavers will provide technical support for the effective implementation of Social Inclusion program at field level. Jeevika with the collaboration of Sightsavers has been promoting different livelihood programs according to the preference and capacity of DPG. The empowerment of persons with disabilities is

being promoted by generating awareness about their rights and entitlements; by economic empowerment through capacity building, financial inclusion and employment generation. Through capacity building the members of DPG have been trained for skill development in various livelihood activities such as Bangle making, Mushroom cultivation, Candle Making, Achar and Papad making, Incense making, Dairy products, Mobile repairing, Electric repairing, Solar lamp assembling and Distribution, Notebook making, Tailoring, Sanitary Napkin making etc. The financial inclusion of persons with disabilities has opened the window of financial services such as access to savings, credit and insurance etc.

During the phase-I (2015-2020), the work has been started in 19 selected blocks of 6 districts-Gaya, Nalanda, Muzaffarpur, Madhubani, Khagaria and Purnia on pilot basis. In these districts, all persons aged between more than 2 years to 55 years with 21 disabilities included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Act, 2018 were identified based on the participatory and self-identification method. The need assessment survey of identified persons has been completed. In the next stage, Persons with disability Self Help Groups (PWD SHGs) have been formed with the size of 5-10 members each. In case of identified minor children with disabilities and children with severe intellectual disabilities, guardian/care taker is made as their representative in DPGs. These PWD SHGs were included under the Village Organizations (VOs). During 2016-2019, total 6456 Persons with disabilities were identified and 963 Disabled Person Groups (DPGs) were formed and 91 DPGs were included in VOs.

During the Phase-II of Social Development interventions for Person with disabilities (PwDs), BRLPS has approved the capitalization in form of Revolving Fund of an amount Rs.50,000 and Initial Capitalization Fund of amount Rs.60,000 to 5000 SHGs from all the districts of Bihar. Till March, 2022 total 3158 DPGs were formed out of which currently 992 DPGs opened their savings account. So far total 573 DPGs received the RF amount and 409 DPGs are capitalized with ICF. This RF and ICF amount received by DPG groups is used for inter loaning among the members and finally to promote the livelihood of persons with disabilities.

जीवन के लिए हरियाली जरूरी

मनीष कुमार, प्रबंधक - संचार, वैशाली

वृक्ष का मानव जीवन में बड़ा महत्त्व है। इसके बिना एक पल भी हम जिन्दा नहीं रह सकते। वृक्षों से मिलने वाले ऑक्सीजन से हम सभी की सांसें चलती हैं। आज के परिवेश में एक ओर जहाँ हानिकारक गैसों के चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो दूसरी ओर पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। यह सम्पूर्ण जीव–जगत के लिए खतरा पैदा करने वाली समस्या है। इससे बचाव के लिए एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा रोपण हीं उपयुक्त एकमात्र साधन है।

वृक्षारोपण के महत्त्व :–

- वृक्षारोपण से तात्पर्य वृक्षों के विकास के लिए पौधों को लगाना और हरियाली को फैलाना है।
- पर्यावरण को बेहतर बनाने में वृक्ष और पौधे मदद करते हैं।
- यह हवा को शुद्ध करना, पानी को संरक्षित करना इत्यादि तरीकों से समग्र पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं।
- अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वृक्षारोपण मदद करता है।
- पेड़–पक्षियों के साथ–साथ जानवरों के लिए भी आवास के रूप में सहायता करता है।
- पृथ्वी पर पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखने के लिए पेड़ अति महत्वपूर्ण हैं।
- हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और ऐसा करने के लिए आस–पास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए।

जल जीवन हरियाली योजना के तहत वर्ष 2021–22 में वन विभाग के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा मिशन 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने में जीविका ने अपनी अधिकाधिक भागीदारी के लिए लगातार प्रयास किया। इसी प्रयास के तहत वित्तीय बर्ष 22 –23 में कुल 87.1 लाख बृक्षारोपण किया गया है।

उपलब्ध करवाए गए पौधों में फलदार व काष्ठीय दोनों प्रकार के पौधे हैं। फलदार पौधों में आम (बीजू), अमरुद, कटहल, जामुन, बेल, सहजन, निम्बू, आवंला, शरीफा, इमली, काजु तथा काष्ठीय पौधों में अर्जुन, यूकेलिप्टस, गम्हार, काला, शीशम, महोगनी, सागवान, सेमल, सिरीस, अमल्तास, अगस्त्य, छटवन, जरहुल, कचनार, पेलटोफॉर्म, बकेन, चकुंदी, करंज, महुआ, नीम इत्यादि शामिल है।

वितरित किये गए पौधों (वित्तीय वर्ष 22–23) का जिलावार विवरण निम्नलिखित है –

क्र.सं	जिला का नाम	वितरित किये गए पौधों की संख्या
1	अररिया	114033
2	अरवल	47942
3	औरंगाबाद	201941
4	बांका	373520
5	बेगुसराय	140584
6	भागलपुर	184555
7	भोजुपर	170571
8	बक्सर	123312
9	दरभंगा	150400
10	गया	96738
11	गोपालगंज	178217
12	जमुई	252815
13	जहानाबाद	0
14	कैमूर	255710
15	कटिहार	205323
16	खगडिया	140000
17	किशनगंज	140000
18	लखीसराय	118489
19	मधेपुरा	221728
20	मधुबनी	581406
21	मुंगेर	129427
22	मुजफ्फरपुर	481159
23	नालंदा	330767
24	नवादा	114209
25	पश्चिम चंपारण	524018
26	पटना	283078
27	पूर्वी चंपारण	504924
28	पूर्णीया	195515
29	रोहतास	135299
30	सहरसा	203170
31	समस्तीपुर	391545
32	सारण	382399
33	शेखपुरा	95787
34	शिवहर	80531
35	सीतामढ़ी	366401
36	सिवान	185000
37	सुपौल	405096
38	वैशाली	238480
कुल		**8710478**

पर्यावरण की सुरक्षा के संकल्प के साथ वृक्षारोपण हेतु पुरे बिहार में जीविका दीदियों ने सबसे पहले 'गड्ढा खोदो अभियान' की शुरुआत की। विभिन्न प्रखंडों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा अपने जमीन और सरकारी जमीन पर गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोदो अभियान को लेकर जीविका दीदियों में काफी उत्साह देखा गया । सभी प्रखंडों में पौधारोपण हेतु लक्ष्य के अनुसार दीदियों ने गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदो अभियान का काफी व्यापक असर देखा गया और दीदियों ने अपनी शत–प्रतिशत सहभागिता दी। अभियान की सफलता में कैडर, जीविकाकर्मियों के साथ सभी चयनित ड्राप प्वाइंट मैनेजर की भी सक्रिय भूमिका रही।

पौधारोपण का यह कार्य पर्यावरण के संरक्षण के साथ–साथ जीविका समूह से जुड़े सदस्यों के परिवार के पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सहयोग प्रदान करेगा। जीविका दीदियों द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को "हरित जीविका, हरित बिहार" के नाम से भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

बिहार के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए पिछले कुछ सालों से जीविका दीदियों द्वारा सघन पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जीव जगत की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक पौधा प्रति वर्ष अवश्य लगाना चाहिए।

कोशी की धरती पर मलबरी की खेती

राजीव रंजन, प्रबंधक - संचार, पूर्णियाँ

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेवा यात्रा के दौरान वर्ष 2013 में सुपौल जिले में की जा रही शहतूत की खेती एवं मलबरी रेशम कीट पालन का अवलोकन किया था। यहां उन्होंने शहतूत (मलबरी) की खेती करने वाले किसानों एवं बुनकरों के साथ बातचीत की। मलबरी किसानों के सराहनीय प्रयास को देखते हुए विभागीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कोशी एवं पूर्णियाँ प्रमंडल में शहतूत की खेती एवं उससे संबंधित उद्योग के विकास के लिए परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की। कोशी एवं सीमांचल क्षेत्र को मलबरी रेशम उत्पादन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ। तद्नुसार रेशम उद्योग विभाग के पदाधिकारियों द्वारा रेशम वैज्ञानिकों, प्रसार से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा इस कार्य में संलग्न विभिन्न प्रकार के उद्यमियों के सुझावों के आधार पर परियोजना में शहतूत की खेती, कीटपालन, सूत एवं वस्त्र उत्पादन को भी समेकित की गई। तत्पश्चात् दिनांक 10.02.2014 को मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना ''कौशिकी'' के रूप में स्वीकृत की गई।

जलवायु एवं मिट्टी की अनुकूलता के हिसाब से बिहार राज्य के उत्तर–पूर्वी जिला मलबरी की खेती एवं रेशम कीट पालन के लिए अनुकूल है। यही कारण है कि इस परियोजना के तहत कोशी एवं पूर्णियाँ प्रमंडल के सभी सात जिलों यथा – सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया को मलबरी एवं रेशम उत्पादक जिले के रूप में चयनित किया गया । तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2014–15 से परियोजना के पहले चरण में सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना प्रारंभ की गई। परियोजना का विस्तार द्वितीय चरण में वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिला में किया गया।

परियोजना का मूल उद्देश्य राज्य में मलबरी रेशम का उत्पादन

बढ़ाने के साथ–साथ इस कार्य से जुड़े हजारों परिवारों की आय में वृद्धि करना है। 'जीविका'' द्वारा उत्प्रेरित महिला किसानों को शहतूत की खेती के माध्यम से रेशम उत्पादन हेतु मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण में सहयोग किया जा रहा है।

प्रत्येक जिले में कार्यक्रमों के संचालन के लिए जीविका एवं हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग एवं मनरेगा मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना के क्रियान्वयन में मदद कर रहे हैं। मलबरी की खेती एवं कीट पालन हेतु किसानों का चयन तथा प्रशिक्षण जीविका द्वारा किया जाता है। वहीं सैपलिंग उत्पादन, पौधारोपण एवं रख–रखाव में जीविका के साथ ही मनरेगा की मुख्य भूमिका होती है। इसी तरह कीट पालन से जुड़े उपकरणों की आपूर्ति एवं तकनीकी सहायता हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय द्वारा प्रदान किया जाता है।

मलबरी के गुणवतापूर्ण उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित किसानों द्वारा मलबरी की खेती हेतु पौधारोपण कार्य किया जाता है। आधा एकड़ खेत में मलबरी के 2700 पौधे लगाए जाते हैं। पैसे का भुगतान मनरेगा मद से किया जाता है। इसके अलावा मनरेगा से ही किसानों को 100 दिनों के मानव श्रम की मजदूरी एवं बोरिंग के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त किसानों को दूसरे एवं तीसरे वर्ष भी मलबरी पौधों की देखभाल के लिए मनरेगा निधि से प्रत्येक 100 मानव दिवस के श्रम का भुगतान किया जाता है।

वृक्षारोपण कर चुके किसानों में से निकटवर्ती 5 किसानों का एक समूह जीविका द्वारा बनाया जाता है। प्रत्येक किसानों के वृक्षारोपण वाले भूखण्ड पर जीविका द्वारा मनरेगा निधि से बोरिंग की व्यवस्था की जाती है। एक इकाई के लिए विद्युत/डीजल पम्प सेट के क्रय की लागत 62,500 रुपये स्वीकृत है, जिसमें से 75 प्रतिशत राशि राज्य योजना एवं शेष 25 फीसदी लाभुक के अंशदान से व्यय होता है।

जिन किसानों ने इस परियोजना के तहत मलबरी का वृक्षारोपण किया है, वे कीटपालन प्रारंभ करने के पात्र हैं। कीटपालन करने के लिए कीटपालन उपकरण जैसे– स्टैंड, ट्रे, डाला, चन्द्रिका डाला आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है। उपकरण क्रय की लागत 25,000 रुपये स्वीकृत है, जिसमें से 75 फीसदी राज्य योजना से एवं 25 फीसदी लाभुक अंशदान से प्राप्त होता है। रेशम कीटपालन हेतु किसानों को रोग मुक्त चक्ता (अंडा/ डी॰एफ॰एल॰) की आपूर्ति की जाती है। मलबरी कीटपालन के लिए एक खास प्रकार का कीटपालन घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कीटपालन घर की लागत 1,20,000 रुपये स्वीकृत है, जिसमें से 50 प्रतिशत राज्य योजना से उपलब्ध कराया जाता है एवं शेष 50 फीसदी राशि लाभुक द्वारा लगाया जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर मलबरी किसानों द्वारा कोकून का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम कीट का जीवन चक्र चार अवस्थाओं–अंडा, लार्वा (कीड़ा या कीट) प्यूपा एवं तितली में चलता रहता है। अंडे से नन्हें कीट निकलते हैं, जिनका भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्तियाँ है। व्यस्क कीट अपने मुँह से एक विशेष प्रकार का लार निकालते हैं, जो हवा के संपर्क में आकर धागे का रूप ले लेता है। तीन दिनों के अंदर यह लार एक कवच का रूप ले लेता है और कीड़ा स्वयं प्यूपा में परिवर्तित होकर इस कवच के अंदर कैद होकर अपने को सुरक्षित कर लेता है। यही कवच कोया कहलाता है, जो हमारे लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। 10–12 दिनों में यह प्यूपा तितली का रूप लेकर अपने कवच से बाहर आ जाता है और मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हेतु अनुपम भेंट छोड़ जाता है। नर एवं मादा तितली मैथुन करते हैं। मादा तितलियाँ अंडा देकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। लेकिन यह चक्र प्रकृति में अनवरत रूप से जारी रहता है। प्रकृति के इस रहस्य को जानते ही मनुष्य ने इसका व्यावसायिक कीटपालन करना शुरू कर दिया, जो आज पूरे विश्व में रेशम उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है।

किशनगंज, पूर्णियाँ, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और कटिहार में उत्पादित मलबरी कोकून का धागाकरण करने एवं जीविका दीदियों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से किशनगंज में वर्ष 2019 में घोष रीलिंग मशीन की स्थापना की गई है। इस मशीन से प्रतिदिन 50 किलोग्राम कोकून (कच्चा कोकून) का धागाकरण किया जाता है।

पूर्णियाँ जिले के आदर्श जीविका महिला मलबरी रेशम उत्पादक समूह के द्वारा उत्पादित कोकून का धागाकरण व बुनाई करने के पश्चात् डिजाईनर सिल्क साड़ी का निर्माण बाँका जिले के कटोरिया, भागलपुर जिले के नाथनगर एवं पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद एवं वीरभूम जिले के बुनकरों द्वारा कराया गया, जिसके विपणन हेतु विभिन्न शहरों में आयोजित सरस एवं हस्तशिल्प मेला तथा अन्य आयोजनों में स्टॉल लगाकर बिक्री किया जाता रहा है, जिसमें लोगों ने इन सिल्क साड़ियों में विशेष उत्सुकता दिखाई है। रेशम उत्पादक समूहों की सदस्यों ने कोकून की राखी का निर्माण कर रक्षा बंधन के अवसर पर बेचती है।

जीविका दीदियों द्वारा उत्पादित कोकून की बिक्री हेतु कई रेशम उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। वहीं वृहत् पैमाने पर बाजार में मलबरी उत्पाद के विपणन हेतु पूर्णियाँ एवं कोशी प्रमंडल के सभी जिले के कृषकों के निदेशक मंडल ने कौशिकी जीविका महिला मलबरी सिल्क उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन किया है।

Partnership with I-Saksham, Pratham Initiatives and Turn The Bus for Supplementary Education Support for Rural Students

Koyel Das, YP-SD

Background:

Bihar JEEViKA with a history of more than a decade has successfully established several key milestones. One of the major highlights has been achieving benchmark of 10 lakh SHGs with inclusion of 1 crore 20 lakh women as forerunners of positive social and economic change in the social fabric of Bihar.

Women and Children are dichotomous entities. Thus, it has implications on strategies adopted to combat developmental gaps in a holistic manner. Underscoring this fact, JEEViKA has taken up educational initiatives in a collaborative framework with three partner agencies i.e. Pratham Education Foundation, i-saksham and Turn the Bus. The three partners are tweaking the educational equity indicators in different areas of Bihar.

Pratham Education Foundation:

Pratham Education Foundation is an innovative learning organization created to improve the quality of education in India. Primarily, Pratham focuses on high-quality, low-cost, and replicable interventions to address gaps in the education system. In this premise

Education is one of the prime intangible indicators of development paradigm. Therefore, partnership with Pratham, will lead to empowerment of our institutions and will enable mothers to gauge their children's education as well as take necessary action with the stakeholders.

Pratham and JEEViKA are jointly implementing this project in 5 districts of Bihar i.e. Supaul, Gaya, Purnea, Nalanda and W. Champaran.

Moreover, the COVID crisis led to sudden closure of schools thus inhibiting the learning process of marginalized rural poor students. To address this need e-learning with Pratham was started in July 2020 wherein quality learning materiel for primary school going children was shared with more than 20000 children.

In upcoming financial year, 10 more districts would be covered under Pratham e-learning intervention and the plan is to reach 50,000 primary school going children will be mobilized.

i-Saksham:

In partnership between BRLPS and i-Saksham, an education initiative/pilot was started in the year 2019 with 25 female edu-leaders from Jamui and Munger. In 2021 the first cohort of edu-leaders completed their two year fellowship. The key objective of this collaboration is to bring about qualitative change in the existing educational structure both at the micro (student) and macro (institutional) level by facilitating active engagement of CBOs. In other words, this will also ensure strengthening of community led institutions and building of socially responsible entities. The edu-leader, may also be called a 'fellow' is a community education leader who is trained by i–Saksham's team under a fellowship program. Within this fellowship they are trained to run community-learning centers for 2 years wherein they provide min.10 hours of educational support every week to children from marginalized communities.

In the next phase two new districts have been added i.e. Gaya and Muzaffarpur. It will also benefit ultra-poor household beneficiaries under Satat Jivikoparjan Yojana. The goal is to develop 1000 edu-leaders who will teach/benefit 15000 primary school going children. Furthermore, in the process of 2 year fellowship they will be supported in honing their own leadership and life skills

Turn The Bus Digital Classroom

The Turn the Bus and JEEViKA initiative was started as a pilot project for the academic session of Bihar Board (2019-2020) to empower local students/ youths through the process of Digitization of educational content developed by quality teachers from renowned universities. The key objective of systemic change in the grassroots level, there was a fundamental need to understand and address the current demands of the rural community.

The COVID-19 pandemic led to sudden requirement of online learning medium/platforms; this unknowingly matched with the ethos of the partnership. It aided in giving the right momentum to the project and with the introduction of TTB application the collaboration was able to fruitfully mobilize 23k students from class 12th and 10th.

Turn the Bus is envisaged as our potential partner to harness this demand for quality digital education for rural adolescents and youths. This year the partnership is targeting to mobilize 1 lakh students based on the lessons learnt from the introduction of first chapter of app based education in the ecosystem of JEEViKA.

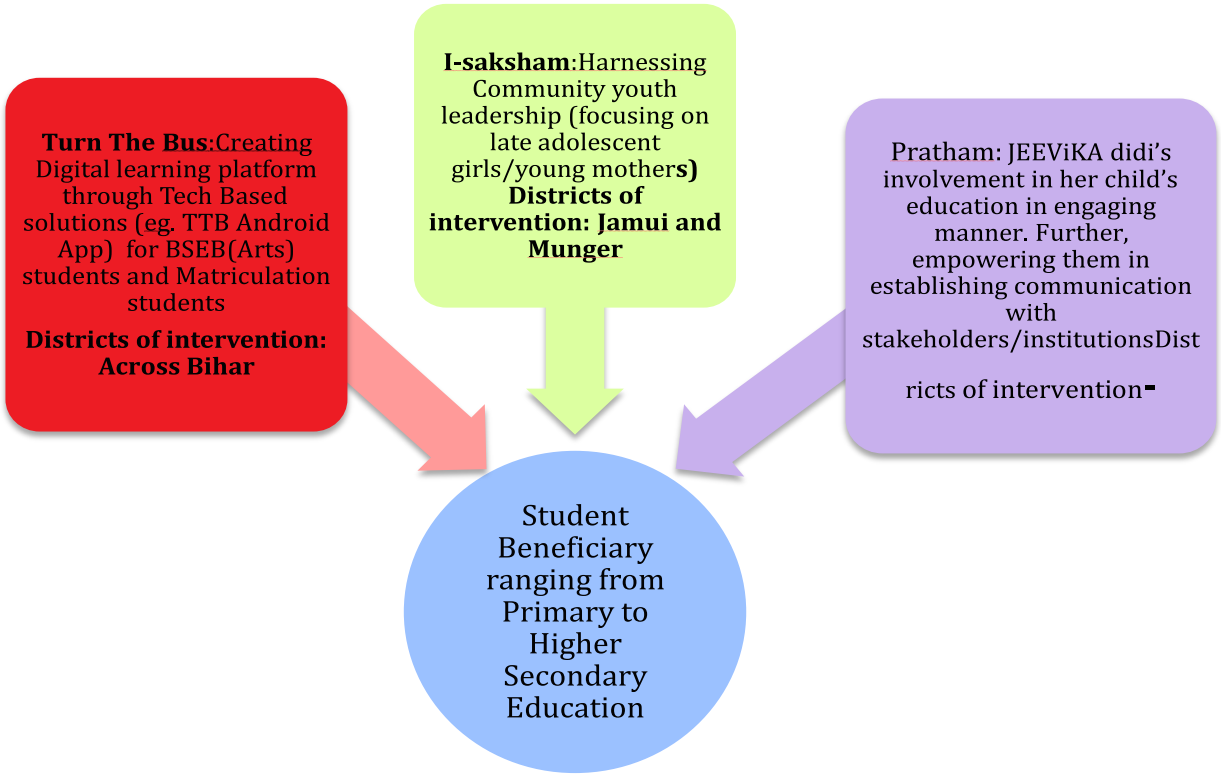

Image1: Graphical Representation of model for the three interventions in their key objective of providing supplementary educational support to children

The matrix below will further elucidate the models and strategies adopted:

Model		
Pratham (w.e.f July 2018)	**i-saksham (w.e.f March 2019)**	**Turn The Bus (w.e.f October 2019)**
• Developing mother-child engagement through interactive learning methods • E-learning platform for primary school going children. This could act as a cushioning during disasters like the covid 19 pandemic	• Harnessing Community youth leadership (focusing on late adolescent girls/young mothers) • Subsequently, benefitting rural primary school going children	• Creating Digital learning platform for BSEB(Arts) students • Promotion of self-learning values among students
Geography		
• Nalanda- Rajgir,Silao,Nagarnausa • Supaul- Raghopur, Pratapganj, Kishanpur • Gaya- Bodh Gaya, Manpur • Purnea- Damdaha, K-nagar • West Champaran- Gaunaha • 10 more Districts have been added for the e-learning initiative	• Jamui- Khaira and Jamui Sadar • Munger- Dharhara and Jamalpur	Across Bihar
Key Outcomes		
• 20 thousand students getting benefitted through e-learning platform	• 22 edu-leaders have successfully completed the fellowship; they have benefitting more than 750 children by supporting in primary education	• 23000 students from class 12 Arts BSEB students benefitted from the Digital platform and appeared for boards in 2022

जागरूकता एवं स्वावलंबन से महिलाओं ने की बराबरी

विकास कुमार राव, प्रबंधक - संचार, सुपौल

बिहार में जीविका परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं में आर्थिक एवं सामाजिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और आजीविका संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन के साथ ही उन्हें समाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक किया जाता रहा है। इसी कड़ी में जीविका समूह से जुड़ी दीदियों को लैंगिंक समानता जैसे संवेदनशील विषयों पर भी जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। यूं तो वर्तमान परिदृश्य में महिला एवं पुरुषों के बीच कई मुद्दों पर बराबरी देखी जा रही है। फिर भी बालिका शिक्षा, दहेज–प्रथा, बाल–विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के अलावा यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रुण हत्या, लड़कियों को सम्पति का अधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अभी भी समाज में जागरूकता लाने हेतु निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। महिलाओं के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर लिंग आधारित भेदभाव से समाज को निजात दिलाने की जरूरत है। यही कारण है कि जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से लैंगिक समानता जैसे विषयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को जागरूक एवं संगठित किया जा रहा है।

स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु निम्न कार्य किए जा रहे हैं:–

- जीविका के सामुदायिक संगठनों से जुड़ी महिलाएं अब अपने स्वयं के नाम से पहचानी जाने लगी हैं, जबकि पूर्व में वे अपने पति या बेटे के नाम पर जानी जाती थीं।
- सामुदायिक संगठन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में महिलाओं की पूर्ण सक्रियता की वजह से उनमें विभिन्न विषयों पर जागरूकता एवं गतिशीलता बढ़ी है।
- समूह के माध्यम से आसानी से ऋण उपलब्ध होने एवं जीविकोपार्जन गतिविधियों से जुड़ने की वजह से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। इन महिलाओं ने ऐसे कई क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ी है, जिसे सिर्फ पुरुषों के एकाधिकार वाला क्षेत्र माना जाता था।
- इससे समाज एवं परिवार में महिलाओं का मान–सम्मान बढ़ने के साथ ही वे अब निर्णयक भूमिका में आने लगी हैं।
- जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों का समाधान निकालना आसान हुआ है।

- सामुदायिक संगठनों की बैठकों में दीदियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, इससे वे मनरेगा, राशन, पेंशन, बीमा आदि सुविधाओं का लाभ उठा पा रही हैं।
- ग्रामीण स्तर पर सभी घरों में शौचालय के निर्माण एवं उसके नियमित उपयोग किए जाने से महिलाओं का मान–सम्मान बढ़ा है।
- शराब बन्दी के माध्यम से घरेलू हिंसा एवं यौन हिंसा में काफी कमी आई है। उल्लेखनीय है कि जीविका दीदियों की मांग पर ही बिहार के माननीय मुख्यममंत्री द्वारा बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की गई थी। यह निर्णय राज्य में महिला सशक्तीकरण को दर्शाता है।
- महिला और पुरूष के बीच आपसी झिझक कम हुई है।
- समूह से जुड़ी निरक्षर दीदियों ने भी अब हस्ताक्षर करना सीख लिया है। इससे उनमें एक आत्मविश्वास की झलक देखी जा सकती है।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर भागीदारी के साथ–साथ उनकी राजनीतिक स्तर पर भी भागीदारी बढ़ी है। समूह से जुड़ी महिलाओं ने बड़े पैमाने पर पंचायती राज संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। साथ ही राज्य में हुए पिछले कई चुनावों में बड़ी संख्या में मताधिकार का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

सामूहिकता से टूटी पुरुषवादी मानसिकता

सिंधवारा प्रखंड अन्तर्गत मुस्कान जीविका महिला ग्राम संगठन से संबद्ध तुलसी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य सावित्री देवी पैसे की तंगी की वजह से अपने घर में आए दिन हो रहे कलह से परेशान थी। सावित्री दीदी कुछ काम करके पैसे कमाना चाहती थी। उसने सामुदायिक संसाधन सेवी यानी सीआरपी के रूप में काम करने इच्छा जाहिर की। पति की सहमति के बाद सावित्री देवी सीआरपी के रूप में कार्य करने के लिए बाहर चली गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब गाँव के अन्य पुरुष उसके पति को ताना देने लगे तो वह अपनी पत्नी को फोन पर काफी भला–बुरा कहने लगा। आखिरकार दीदी बीच में ही काम छोड़कर घर वापस लौटी आई। उसके पति काफी गुस्से में थे। उसने सावित्री दीदी के साथ काफी गाली–गलौच एवं मारपीट किया। इससे वह दुखी होकर मायके चली गयी। सावित्री दीदी के साथ घटित इस घटना के बारे में जब ग्राम संगठन को पता चला तो सभी दीदियों ने इस मामले में सख्त कदम उठाने का फैसला किया। ग्राम संगठन की बैठक में सभी दीदियों ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि समाज में व्याप्त पुरुष प्रधान मानसिकता के खिलाफ वे सामूहिक रूप से आवाज उठाएंगी। दीदियों ने सबसे पहले सावित्री देवी को अपने मायके से घर बुलाया। इसके बाद ग्राम संगठन की एक विशेष बैठक का आयोजन कर इसमें सावित्री देवी और उसके पति दोनों को बुलाया गया। इस बैठक में सावित्री दीदी के पति ने स्वीकार किया कि गाँव के पुरुष ताना देते थे। इस कारण गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। सभी दीदियों ने उसके पति को समझाया कि दूसरों के कहने पर उसे अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि उसकी सहमति से ही सावित्री देवी सीआरपी के रूप में काम करने बाहर गई थी। दीदियों द्वारा समझाने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना उसकी एक बड़ी भूल थी। अब वह कभी इस तरह की गलती नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने ग्राम संगठन की दीदियों को आश्वस्त किया कि अपनी पत्नी के साथ वह हमेशा सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा और उसे किसी भी प्रकार के काम पर जाने से नहीं रोकेगा। सावित्री दीदी बताती है कि उस दिन के बाद से उसके पति के व्यवहार में काफी बदलाव आया। अब वह हमेशा अच्छा बर्ताव करते हैं और घर संबंधी सभी निर्णयों में उसकी सहभागिता होती है। सावित्री देवी अब बेरोकटोक सीआरपी के कार्य से बाहर जाती हैं एवं समूह संबंधी गतिविधियों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेती हैं।

SOCIAL DEVELOPMENT INITIATIVES DURING COVID-19

Shivani Gupta, YP-KMC

In 2021, second wave of COVID-19 hit India and was much more severe and had far greater health implications than the initial wave did in 2020. The mobility restrictions and health implications of the first COVID-19 wave resulted in severe economic shocks throughout India bringing into focus the role of the country's formal and informal institutions in supporting resilience.

JEEViKA left no stone unturned when it came to providing a hand-hold support to its Didis during the most uncertain times of the Covid-19 pandemic. In order to ensure that the every member of JEEViKA had their basic needs fulfilled, many initiatives under Social Development theme were taken which are listed below.

The 'No-Bar Food Security Fund'

A food security intervention called the Food Security Fund (FSF) is designed to help VO members who are potentially credit constrained access large quantities of food grains in a single purchase without exposing them to high interest rates. However, fund was only granted to the SC/ST communities in normal

circumstances, but due to the pandemic situation that had placed each and every community member in the Rural Bihar in a vulnerable situation. It was decided to grant the Food Security Fund of 1 lakh in every Village Organization benefitting each and every JEEViKA Didi. During COVID 3500 VOs have received the FSF more than 45 Lakhs JEEViKA Didi have been benefitted in kind.

Health Risk Mitigation Fund at Immediate Rescue:

The Health Risk Mitigation Fund (HRF) of JEEViKA, operational prior to COVID-19, was extended to all village organizations (VOs) to meet the health requirements in distressing times of COVID-10, with no rate of interest to be applicable for loans taken against the HRF component for the period of March 2020 to September 2020 as well as for previous loans.

Application and Documentation for Ration Card

During Covid-19 pandemic the situation was appalling throughout the country however and horrors faced by the migrants workers of Bihar when they immediately had to leave the cities and walk back to their home. In this situation the only way the government could directly benefit the people was through distribution of ration on subsidized rates to the Ration Card holders. JEEViKA during this time played a very crucial role of collecting applications from people and helped them to complete the entire documentation process. Over 15Lakh Ration Card sanctioned during COVID.

JEEViKA DIDI as an 'IMPACT MAKER' in "Turn the Bus"

Turn the Bus is a Seattle-based nonprofit initiative with a mission to reduce educational inequality with the help of smart phones. They publish high quality content on their app and YouTube channel, accessible via smart phones, to leverage the smart phone wave in India. These initiative are supported via partnerships with JEEViKA. The pandemic took away the pens and books from the children of the poor. At this juncture "Turn the Bus" came as a boon to the children of the rural community who can access these high quality video lessons of standard 10th and 12th at the comfort of their homes in their village hassle-free. Through their participation, JEEViKA Didis have gained a voice and have created an identity beyond their gender roles and able to promote such initiatives going beyond their SHG circle in the entire village. This is how JEEViKA Didi has become an "IMPACT MAKER" in the society. Till now "Turn the Bus" has engaged 22729 views on YouTube and 664 hours of watch time.

Covid-19 Precautions and Management.

Apart from the several listed initiatives the State Disaster Risk Management Authority also provided Covid-19 precautionary and management training to the Masters Trainers of the Community. A total of 7491 trainings were conducted and more than 112365 members were trained. A total of 42678 persons were oriented on Home based Covid-19 Management with the help of WHO, AIIMS and NSHRC team.

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जीविका दीदियां कर रहीं पौधशाला का निर्माण

राजीव रंजन, प्रबंधक - संचार, समस्तीपुर

जल–जीवन–हरियाली अभियान के अन्तर्गत बिहार में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जीविका दीदियों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ''एक जीविका दीदी–एक पौधा'' के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सभी जीविका दीदियों को पौधारोपण के लिए उत्प्रेरित किया गया है। इस प्रकार जीविका द्वारा 'हरित जीविका हरित बिहार' अभियान के तहत 1.5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने हेतु बड़ी मात्रा में शिशु पौधे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना शुरू की गई है। इसके तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मनरेगा द्वारा जीविका दीदियों को नर्सरी आवंटित की जाती है। राज्य के 251 प्रखंडों में पौधशालाओं का सृजन वन विभाग की मदद से किया जा रहा है वहीं शेष 283 प्रखंडों में मनरेगा योजना अन्तर्गत जीविका दीदियों के पौधशालाओं का सृजन किया जा रहा है। परिणामस्वरूप राज्य भर में इस समय कुल 409 दीदी की नर्सरी सफलतापूर्वक संचालित हैं। इसमें से 221 दीदी की नर्सरी वन विभाग की मदद से तैयार की गई है, वहीं 188 नर्सरी मनरेगा की मदद से संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के तहत संचालित दीदी की नर्सरी को सृजित करने से लेकर बीज बुआई एवं पौधे तैयार करने में वन विभाग एवं मनरेगा द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करने के साथ ही सतत निगरानी भी की जाती है। इसके बाद तैयार पौधों को वन विभाग एवं मनरेगा द्वारा ही खरीद लिया जाता है। पुनः ये पौधे जीविका दीदियों को वितरित किए जाते हैं ताकि जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत पौधारोपण हेतु दीदियों को आसानी से पौधे उपलब्ध कराए जा सके। जीविका दीदियों द्वारा संचालित प्रत्येक दीदी की नर्सरी से कम से कम 20 हजार पौधों की आपूर्ति का एकरारनामा हुआ है। इस प्रकार जीविका दीदियों द्वारा करीब एक करोड़ से अधिक पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जैव विविधिता को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं। आम, अमरूद, आंवला, नींबू, नारियल, जामुन, कटहल, सहजन और बेल जैसे फलदार वृक्ष के पौधों के साथ–साथ सागवान, महोगनी जैसे इमारती लकड़ियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण एवं ऑक्सीजन की अधिकतम उपलब्धता हेतु पीपल, नीम, बरगद जैसे औषधीय महत्व के पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। ये पौधे पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ जीविका दीदियों के परिवार की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं आय प्राप्ति का भी माध्यम बना है।

दीदी की नर्सरी से पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ आजीविका संवर्द्धन : मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के तहत 'दीदी की नर्सरी' संचालित करने वाली दीदियों को इस कार्य से अच्छी आमदनी हो रही है। प्रत्येक दीदी की नर्सरी से 20 हजार पौधों की आपूर्ति की जा रही है। इसके बदले में वन विभाग या मनरेगा के द्वारा पिछले वर्ष तक 11 रुपये प्रति पौधे की दर से भुगतान किया गया था। वहीं पौधों को तैयार करने एवं इसके रख–रखाव पर औसतन एक लाख रुपये की लागत आई थी। इस प्रकार नर्सरी के कार्य में दीदी को एक वर्ष में एक से सवा लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा अर्जित हुआ। वहीं इस वर्ष वन विभाग द्वारा 20 रुपये प्रति पौधे की दर से भुगतान किया जाना है। लिहाजा नर्सरी संचालित करने वाली दीदी को इस वर्ष दोगुनी आय हो सकती है। बहरहाल दीदी की नर्सरी की वजह से न केवल पौधारोपण के लक्ष्यों की पूर्ति करना संभव हुआ है बल्कि इससे दीदी के लिए एक नई आजीविका का भी सृजन हुआ है।

दीदी की नर्सरी के सृजन हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया निम्न है–

दीदियों का चयन : दीदी की नर्सरी हेतु दीदियों का चयन संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से किया जाता है। इसमें ऐसी दीदियों का चयन किया जाता है जो स्वयं सहायता समूह का सक्रिय सदस्य है और समूह के नियमों का अच्छी तरह पालन करने के साथ–साथ ऋण वापसी के मामले में उनकी साख अच्छी है। साथ ही उसे खेती–बारी एवं उद्यानिकी के बारे में बुनियादी जानकारी हो। विधवा, पिछड़े समुदाय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की सदस्य दीदी को प्राथमिकता दी जाती है।

प्रशिक्षण एवं सहयोग : दीदी की नर्सरी के लिए चिन्हित दीदियाँ को पौधशाला में पौधे तैयार करने के बारे में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वह पौधशाला की देखभाल अच्छी तरह कर सकें।

नर्सरी की तैयारी : दीदी की नर्सरी योजना के अन्तर्गत क्यारी की तैयारी एवं पौधे हेतु बीजरोपण से लेकर उसकी देखरेख तक की पूरी जिम्मेदारी सीधे दीदी की नर्सरी लगाने वाली संबंधित जीविका दीदी की होती है। पौधशाला से संबंधित सभी प्रकार की खरीद एवं मजदूरों के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी भी जीविका दीदी की होती है।

सभी प्रजाति के 20 हजार पौधों की आपूर्ति : एकरारनामे के अनुसार दीदी की नर्सरी से सभी प्रजाति के कुल 20,000 पौधों की आपूर्ति वन विभाग अथवा मनरेगा को किया जाना है। पौधशाला में 15 सेमी 25 सेमी के पॉलिथीन बैग में कम से कम 3 फिट तक लम्बे स्वस्थ पौधों की आपूर्ति करने की शर्त होती है। पौधों की आपूर्ति प्रत्येक वर्ष जून, जुलाई एवं अगस्त माह में की जाती है। क्योंकि बरसात का मौसम पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अत : नर्सरी की तैयारी तीन माह पूर्व अर्थात मार्च–अप्रैल महीने से ही शुरू कर देना आवश्यक है।

पौधों का भुगतान : वर्ष 2020–21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रति पौधा 11 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। वहीं वर्ष 2022–23 के लिए भुगतान की दर लगभग दोगुना बढ़ाकर 20 रुपये प्रति पौधा कर दिया गया है। पौधा उपलब्ध कराने के बदले मिलने वाली राशि से जीविका दीदियों को अच्छी आमदनी हो रही है। साथ ही जीविका दीदियों द्वारा पौधशाला का निर्माण किए जाने से वन विभाग के लिए स्वस्थ एवं जीवित शिशु पौधों की आपूर्ति करना आसान हो गया। इससे जीविका दीदियों द्वारा सघन स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है।

मनरेगा ने जीविका दीदियों को दी नई उड़ान

विकास कुमार राव, प्रबंधक - संचार, सुपौल

बिहार के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ–साथ बुनियादी ढांचें के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित इन कार्यक्रमों में जीविका दीदियां अहम भूमिका निभा रही हैं। इससे एक ओर जहां गरीब परिवारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, वहीं इससे ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचनाओं एवं उत्पादक परिसंपत्तियों का भी निर्माण हो रहा है। ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक 'महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)' के माध्यम से जीविका से जुड़े परिवारों को रोजगार दिलाने एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। मनरेगा के बहु–आयामी रणनीति के तहत विभागों के साथ अभिसरण कर गरीब परिवारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ–साथ परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है।

100 दिन काम की गारंटी

मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड के माध्यम से 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। मनरेगा के माध्यम से बड़ी संख्या में जीविका दीदियां एवं उनके परिजनों को रोजगार उपलब्ध कराए जा रहा है। जीविका समूह से जुड़े परिवारों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उन्हें साल भर में कम से कम 100 दिन का काम देने की गारंटी दी जा सके। इसके अलावा जीविका दीदियां मनरेगा में मेठ के रूप में भी कार्य करती हैं। साथ ही क्रेच सेंटर का संचालन, कार्य स्थल पर

विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता यथा– मजदूरों को पानी पिलाना आदि के कार्यों के माध्यम से भी जीविका दीदियों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

पौधारोपण

मनरेगा के द्वारा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के तहत जीविका दीदी की नर्सरी तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जिसके तहत जीविका दीदियों को पौधा लगाने से लेकर उसकी सुरक्षा, पौधे की देखभाल एवं उसकी बिक्री में सहयोग प्रदान किया जाता है। नर्सरी में बड़ी मात्रा में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन पौधों को मनरेगा द्वारा खरीदा जाता है। साथ ही इन पौधों को मनरेगा योजना के तहत वन लगाने वाले छोटे–छोटे किसानों को वितरित किया जाता है। वन लगाने के साथ ही मनरेगा द्वारा वन पोषकों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार मनरेगा के माध्यम से पौधारोपण के क्षेत्र में जीविका दीदियों के लिए रोजगार का अवसर सृजित करने के साथ ही परिसंपत्ति का निर्माण किया जा रहा है।

तालाबों का प्रबंधन एवं जीविकोपार्जन

मनरेगा द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नए तालाबों का निर्माण एवं पुराने तालाबों के जीर्णोद्वार का कार्य किया जा रहा है। इन तालाबों को जिला प्रशासन के माध्यम से जीविका को हस्तांतरित किया जा रहा है। जीविका दीदियों द्वारा इन तालाबों का सतत् रख–रखाव एवं प्रबंधन का कार्य किया गया है। जीविका दीदियां उत्पादक समूह का गठन कर इन तालाबों में मत्स्य पालन, बत्तख पालन, मखाना की खेती जैसी जीविकोपार्जन गतिविधियां चला रही हैं। इससे दीदियों के लिए आजीविका का सृजन हो रहा है और उनके घर की आय बढ़ी है।

पशु शेड का निर्माण

मनरेगा के माध्यम से जीविका समूह से जुड़े परिवारों के घर बड़ी संख्या में पशु शेड का निर्माण कराया गया है ताकि इन परिवारों द्वारा गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि का कार्य कर अपने घर की आमदनी बढ़ा सके।

कलस्टर फैसिलिटेशन टीम (सीएफटी)

सीएफटी का उद्देश्य मनरेगा के कार्यों में गुणात्मक परिवर्तन लाकर ग्रामीणों के लिए गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों का सृजन करना है। जीविका द्वारा मनरेगा के साथ मिलकर कई प्रखंडों में सीएफटी का कार्य किया जा रहा है।

A Centre for Accessing Entitlements and Women Justice

Didi Adhikaar Kendra

Niraj Kumar Singh, PM-SDE

Background:

Government has announced several schemes /programs and benefits for marginalized communities to combat the advarce situation in the country. Though schemes are being announced to support the people, the marginalized communities like tribals, dalits, women, minority communities face challenges in accessing these programmes and entitlements. Several challenges like lack of information, complicated processes, leakages in the pipeline, lack of supporting documents come in the way. These hurdles become manifold when there is restricted movement both due to the fear of the pandemic as well as or migration of earning male members .Nationwide lock down due to COVID-19 has also impacted different sections of the society in different ways. Households dependent on remittance or daily wages suffered most as they did not have any cash flow to support the daily expenses. Now more than ever, in the context of the pandemic and associated constraints on mobility, there is a need for stronger, bottom-up processes of governance at the local level to take charge of relief and rebuilding measures. Besides entitlements violence against women, and other gender related issues also increased significantly. Education of girl child and child marriage emerged as key social issues. To address these Gender and Entitlement related issues there is a need to establish one nodal center at block premises to coordinate the issues to redress without much delay and system related hurdles i.e Didi Adhikar Kendra . All above has to be built up over experience of Haqdarshaq (HD) Pilot project as below .

The objective of Haqdarshaq the program was to provide benefits and government entitlements to the poorest of the poor community people. One of the most significant impacts of the program has been in breaking the barrier of Didis not taking service charges

from the community, and the community had no culture of giving service charges to Didis. Didis are stepped ahead to transform their own lives by increasing livelihood income. HDs have now served households across five blocks of Sheohar district in a very short span of the implementation phase in this pilot project by benefiting them with multiple documents and various eligible schemes. Now citizens can get the information sitting at home for which schemes they are entitled to. Earlier the community was not aware of the schemes and their entitlements before the project implementation. Now with the HD app interventions, they can get information like the fee for applying to any scheme and what supportive documents are required to apply (offline/ online). This has also enhanced the level of confidence of Didis by meeting concerned government officials and visiting various departments at regular intervals.

HESPL team and Haqdarshak (HD) have extended their handholding support to the community people in getting free distribution of food grains under covid – 19 schemes. HDs have also advocated for the community people in mitigating apprehension/ myths related to vaccination & have ensured maximum support for getting the community vaccinated. Since the inception of the project, we have tried to enhance HDs understanding and skills in using digital tools, HD apps, and build their capacity by providing handholding support in the application process for various schemes/ documents. In this initiative we felt the need of collective action for pending issue and high technology cost. So Didi Adhikar Kendra initiative would include this collective action component with low technology cost.

Objective:

The goal of this initiative is to support the marginalized household to access entitlements and women justice as an agenda through collaboration of their collectives with the PRI and the Government departments. Focus will be on establishing an effective delivery system of social protection schemes in convergence with the stakeholders besides other gender based issues i. alcohal prohibition, violence against women, girl child education and adolescent issues. The project will have direct implications on the welfare of women, PWDs and children.

Core Program Interventions:

The Bihar Rural Livelihoods Promotion Society will work in close collaboration with expert agency / NRLM and establish systems and processes for Community institution led Entitlements and gender issue facilitating Hubs at the Panchayat level to be known as Gram Panchayt Help desk and block level Didi Adhikar Kendra . The Help Desk will also draw support from the Community Service Centers (CSCs) to clear the blocks coming up in the documentation process of the social protection schemes.

The GPHD member (Adhikar Sakhi) would introduce a digital app to the CLF and the VO and collaborate with the institutions for village level mobilization of needy women. Special Cader Adhikar Sakhis working in the CLFs will be trained to collect the data/ issues and identify the needs of the needy community in terms of social protection schemes either obtained thorough Village Poverty Reduction Plan / or during community meeting or through Gender Point Persons. Five Adhikar Sakhis one per Village (Incentivized cadres of CLF) from this fund will provide hand holding support to CLF /SAC members and GPP. Identified Issue will be monitored on the status of application at GPHD with the help of Adhikaar Sakhis and resolved with the help of Block level entitlement Hub (BEH). The existing social mobilization and the BRLPS project teams present in the area will have to create a community-led mechanism to trigger women collective action around access to various government schemes and programs for vulnerable households and specific sections such as pregnant and lactating women and adolescent girls. The CLFs will facilitate the process with the Help desk setup at the Panchayat level, the CSCs, and the government departments to strengthen the supply side besides Didi adhikar Kendra and state helpdesk .

Gender Integration in BRLPS-JEEViKA

Partnership between BRLPS and Centre for Catalyzing Change's Sakshamaa Initiative

Center for Catalyzing Change (C3)

C3's Sakshamaa1 is collaborating with the Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPs) – JEEViKA to support their gender integration efforts, in line with the gender operational strategy envisaged by the National Rural Livelihoods Mission, Government of India. This collaboration rests on the belief that while women's collectives have emerged as a promising strategy for empowerment, especially in the domain of livelihoods, societal and patriarchal barriers are a significant barrier that cut across the family, community and institutional domains, limiting women's agency. Key to collectivization efforts, therefore, is system level capacities to integrate gender transformative approaches in strategy and planning, which in turn will unlock pathways towards greater gender equity, agency, and progressive norms.

C3's Sakshamaa is undertaking the following activities to build institutional gender salience (within JEEViKA and community institutions) and capacities through intentional policies, protocols, resources, budgets, and structures, that promote a gender equitable consciousness, competence, and action, while also simultaneously strengthening a bottom-up groundswell of women and girls' voices and demands. In order to ensure gender responsive institutions, we will operationalize Gender Desks, led by women, for women and girls, where women leaders have information and resources, and are prepared to respond to immediate community needs. Gender Desks created and managed at the Cluster Level Federation (CLF) level, will have upstream linkage to support services and entitlement delivery, and downstream linkages with Village Organisations (VOs) and SHGs. This will establish a framework for last mile service delivery on girls' education, and livelihood entitlements, as well as frontline support services on gender-based violence (GBV) for women and girls in rural communities.

Key Activities under this partnership include:

State Level Gender sensitization training and capacity building of JEEViKA staff at the State level

Gender Desks Activating Gender Desks (at the CLF level), Gender Forums (at Panchayat and District levels), and developing Gender Action Plans to

Community Leadership Leadership and gender sensitisation capacity building of Social Action Committee members at CLF and VO level, as well as newly appointed Gender

Implementation Area:

Cluster Level Federations	11			
Blocks	4	Meenapur, Bochaha	Rajgir	Dhanarua
Districts	3	Muzaffarpur	Nalanda	Patna

Outcomes Envisaged:

System Level

i. Enhanced capacity to respond to women and their collective institutions
ii. Catalyze systems that enable women to claim their rights and entitlements
iii. Integrate a gender lens across activities, strategies, and departments

Federation Level

i. Greater CLF capacity, resources - on girls education, child marriage, gendered violence
ii. Convergence established between different government departments to address gender entitlements, services

Evaluation:

To examine process and adaptation of gender-sensitized training and capacity-building programs and how it helps in shifting gender norms and mainstreaming gender action plans in key activities of JEEViKA. This program will be externally evaluated by the Population Council India with the following aims:

System-level JEEViKA staff/ program managers

- To examine process and adaptation of gender-sensitized training and capacity-building programs and how it helps in shifting gender norms and mainstreaming gender action plans in key activities of JEEViKA

Collectives Federation Level (CLF/ VO-SAC, PRIs and other key stakeholders)

- To measure change attributable to gender integration programming on VO/SAC members' attitudes and awareness around
- gender roles
- access to social entitlements;
- girls' education and child marriage;
- women and girls' agency and
- gender-based violence and redressal mechanisms
- To examine improvement in community-level engagement with PRIs and other support services

Process monitoring

Measure progress on Gender Integration through Program Monitoring and Evaluation

दीदी की कहानी दीदी की जुबानी

केस–1 दीदी की नर्सरी

दीदी की नर्सरी से बदली मंजू की जिन्दगी

समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड अन्तर्गत विरसिंहपुर निवासी 48 वर्षीय मंजू देवी महज छठी पास हैं। वर्ष 2017 में वह जीविका से जुड़ी। जीविका से जुड़ने से पूर्व दीदी खेती–बाड़ी का कार्य करती थीं एवं उनके पति शिव कुमार महतो घर पर ही किराना का दुकान चलाते थे। आर्थिक संकट के बीच जीवन की गाड़ी चल रही थी। इन्हीं कठिनाईयों के बीच जब मंजू देवी जीविका से जुड़ी तो उनके जीवन में काफी बदलाव आया। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

मंजू देवी कहती हैं कि – 'जीविका ने ना केवल उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान किया बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने का कार्य किया।' मंजू बताती हैं कि जब जीविका से जुड़ी तो बामुश्किल बचत कर पाती थीं। फिर धीरे–धीरे जीविका द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण का उपयोग करते हुए जहां पति के दुकान की पूंजी बढ़ाई, वहीं अपनी बेटी की शादी भी किया। समूह एवं ग्राम संगठन से लिए गए ऋण को भी मंजू देवी वापस कर रही हैं। मंजू देवी बताती हैं कि इसी बीच उनके पति का कृषि उद्यमी के रूप में चयन किया गया और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के बाद पति को कीटनाशक बेचने का लाईसेंस भी मिल गया। अब मेरे पति गांव के लोगों को कृषि संबंधी मदद पहुंचाने के साथ कीटनाशक बेचने का कार्य भी कर रहे हैं। मंजू बताती हैं कि जब पति को कृषि उद्यमी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा।

मंजू देवी आगे कहती हैं कि इसी बीच उन्हें जीविका की तरफ से दीदी की नर्सरी संचालन के लिए चयनित किया गया। दीदी की नर्सरी के संचालन के लिए चयनित होने के बाद मुझे प्रशिक्षित किया गया, प्रशिक्षण के बाद मैंने कार्य प्रारंभ किया। इस कार्य में मेरे पति एवं बच्चों ने भी मेरी काफी

मदद की। पिछली बार लगाए गए पौधों को विभाग द्वारा खरीदा गया, जिससे मुझे काफी लाभ हुआ। इस बार भी मेरे नर्सरी के पौधों को विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है।

मंजू देवी बताती हैं कि उन्हें इस कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है और अब उनके इस कार्य एवं पति के कार्य से घर की आमदनी औसतन 15 हजार से ज्यादा हो गयी है। घर की बढ़ी आय से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। मंजू यह बताते हुए मुस्कुरा देती हैं कि अब वह अपने परिवार के लिए पक्का का मकान बना रही हैं। दीदी के पीछे उनका अर्द्धनिर्मित घर मंजू देवी के मुस्कुराहट में उनका साथ देता है।

मंजू देवी कहती हैं कि इस कार्य के लिए भी उन्होंने 2021 में जीविका से 50 हजार का ऋण लिया। इस ऋण को भी वह धीरे–धीरे लौटा रही हैं। बातचीत के बीच ही वन विभाग की गाड़ी उनके नर्सरी के पौधों को लेकर रवाना हो चुकी है लेकिन गाड़ी के डाला में बंद पौधे उनके जीवन के बदलाव की कुंजी साबित हो रहे हैं।

केस–2 **ग्राम संगठन की पहल**

फूलो देवी का प्रयास शराब बंदी की ओर

चांदनी समूह की सदस्य फूलो देवी सुदामा ग्राम संगठन से जुड़ी हैं। फूलो देवी ग्राम संगठन की अध्यक्षा हैं। ग्राम संगठन दक्षिणी बहारवा, चेरखेरा पंचायत, अलौली प्रखंड खगड़िया में है। इस ग्राम संगठन के अंतर्गत कुल 26 लोग शाराब के कारोबार से जुड़े हुए थे। जिनके कारण शराब बिक्री चेरखेरा, शहरबन्नी, मेघौना एवं जगमोहरा पंचायत में हो रहा था। शराब के बुराइयों और बुरे प्रभाव से अनजान बूढ़े–बच्चे एवं जवान इसके प्रभाव में आकर अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे थे तथा अपने परिवार एवं अन्य लोगों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली–गलौज एवं मार पीट करते थे।

इधर फूलो देवी के नेतृत्व में ग्राम संगठन सशक्त हो रहा था। एक दिन फूलो देवी के नेतृत्व में ग्राम संगठन की कुछ दीदियों ने शराब व्यापार से जुड़े लोंगों को शराब उत्पादन एवं बिक्री बंद करने के लिए प्रेरित किया परन्तु शराब के ठेकेदारों ने एक नहीं सुनी। एक दिन फूलो देवी ने ग्राम संगठन की कुछ दीदियों के साथ इसकी लिखित शिकायत स्थानीय थाने में की। जिसके बाद स्थानीय पुलिस एक दिन सुदामा ग्राम संगठन के क्षेत्र में पहुंच कर कुछ शराब बेचने वालों की धड़–पकड़ की एवं कुछ शराब के भट्ठियों को नष्ट भी किया। इस घटना से जीविका दीदियों में उत्साह भर गया। यह सूचना सभी ग्राम संगठनों में पहुंचते ही अन्य ग्राम संगठनों की दीदियों द्वारा फूलो देवी को सहयोग किया जाने लगा। यही नहीं फूलो देवी के नेतृत्व में शराबबंदी को लेकर मुहिम चलाया गया। कुछ दीदियां शराब के भट्ठियों को तोड़ने हेतु एकत्रित हो गयी जिसकी भनक शराब के ठेकेदारों को लग गयी। सभी दीदी एकत्रित होकर कुछ शराब भट्ठियां तोड़ ही रही थी कि उनके ऊपर अचानक शराब के माफियाओं द्वारा पत्थर से हमला बोल दिया गया। इस घटना में फूलो देवी का सिर भी फट गया तथा कई दीदियों को चोटें भी आईं। उक्त घटना की लिखित शिकायत ग्राम संगठन की अध्यक्षा फूलो देवी द्वारा स्थानीय थाने में की गई। इधर शराब के ठेकेदारों ने भी जीविका दीदियों के खिलाफ केस कर दिया जिसमें दीदियों के ऊपर मारपीट एवं चोरी का आरोप लगया गया।

एक दिन फूलो देवी एवं ग्राम संगठन एवं कुछ दीदियां पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को विस्तृत रूप से घटना का जिक्र करते हुए लिखित शिकायत की। पुलिस अधीक्षक ने फूलो देवी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना तथा तत्काल संबंधित थाने को निर्देश दिया कि जीविका के दीदियों पर लगाए गए आरोपों की जांच कर मामले का त्वरित कार्रवाई करें एवं सभी शराब के ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश निर्गत किया गया कि कोई भी शराब बनाते या बेचते पकड़े गए तो उनके ऊपर 50,000 रू. जुर्माना लगाया जाएगा एवं जेल भी भेजा जाएगा। फूलो देवी के अथक प्रयास से सभी दीदियों के ऊपर लगाए गए आरोपों को समाप्त कर दिया गया एवं सभी शराब के भट्ठियों को तोड़ दिया गया। इस प्रकार से फूलो देवी सभी दीदियों का आदर्श बन गईं तथा अन्य ग्राम संगठनों में भी शराब बंदी की मुहिम में सहयोग करने लगी। इस प्रकार फूलो देवी समाज के लिए आदर्श बन गईं।

केस–3 सीखे और सिखाएं

जीविका और आई-सक्षम की संयुक्त अनोखी पहल

जमुई जिला का नाम सुनते ही मन में बस एक ही छवि उभर कर सामने आती है। वह है– नक्सलवाद की। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि यह जिला नक्सलियों का गढ़ है। लेकिन बदलते समय के साथ अब इस जिले की तस्वीर भी बदल रही है। जब से ग्रामीण इलाकों में जीविका ने काम करना शुरू किया है, यहाँ के लोग जागरूक होने के साथ–साथ शिक्षित एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 'आई–सक्षम' की। आई–सक्षम जीविका के साथ मिलकर जीविका दीदियों के बच्चों को न सिर्फ शिक्षित कर रही है बल्कि इन्हीं बच्चों को सक्षम एडू लीडर बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद कर रही है।

आई–सक्षम एक एनजीओ है, जो पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा का दीप जलाने का प्रयास कर रही है। आई–सक्षम और जीविका के बीच 6 मार्च 2019 को अनुबंध किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से समुदाय को सशक्त बनाना। जीविका समूह की वैसी दीदियाँ, जिनके बच्चे जागरूकता एवं गरीबी के कारण स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उन्हें एक जगह पर इकटठा करके शिक्षित करना है। इसके लिए समुदाय के परिवारों से ही सक्षम एडू लीडर का चयन किया गया, जिन्हें पटना में सात दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। आई–सक्षम और जीविका की संयुक्त पहल से इन फेलोशिप प्रोग्राम के सपन्न होने के बाद एडू लीडर को जीविका के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सम्मानित भी किया गया।

जीविका के साथ 2019 में अनुबंध के पश्चात् आई–सक्षम ने राज्य के दो जिले मुंगेर और जमुई में गरीब निर्धन परिवारों के बीच काम करना शुरू किया। 2019 में इस फेलोशिप की शुरुआत की गई और यह सितम्बर 2021 में समाप्त हो गया। एकरारनामा के पहले चरण में जीविका के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। जीविका के माध्यम से इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत तीन लाख उनचालीस हजार की राशि भी जारी की गयी।

आई–सक्षम और जीविका के बीच 2021 में दूसरी बार अनुबंध किया गया, जिसके तहत राज्य के चार जिलों को शामिल किया है। जिसमें जमुई और मुंगेर के साथ गया व मुजफ्फरपुर को भी शामिल किया गया है। इस दूसरे फेलोशिप प्रोग्राम में राशि की उपलब्धता स्वयं आई–सक्षम के द्वारा की जा रही है।

आई–सक्षम ने जीविका के साथ मिलकर समुदाय के वैसे बच्चों को लक्षित किया, जो शिक्षा से वंचित थे एवं जागरूकता एवं गरीबी के कारण स्कूल जाने से असमर्थ थे। आई–सक्षम ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया कि राज्य के पिछड़े जिलों के ग्रामीण इलाको में रहने वाले बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। साथ ही वैसे स्कूलों को लक्षित किया गया, जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी। ऐसे स्कूल जहाँ शिक्षकों की कमी थी, वहां पर केन्द्र बनाकर एडू लीडर को पढ़ाने के लिए भेजा गया।

जीविका और आई–सक्षम के बीच समझौता होने के बाद जिले के दो प्रखंडों– जमुई सदर और खैरा में काम शुरू किया गया। जमुई सदर और खैरा प्रखंड के दो संकुल स्तरीय संघ स्वाभिमान और मुस्कान के द्वारा आवेदन के माध्यम से एडू लीडर का चयन किया गया। एडू लीडर का चयन समुदाय के परिवारों से ही किया गया। आई–सक्षम का लक्ष्य है 'सीखे और सिखाएं'। इसी को ध्यान में रखते हुए चयनित एडू लीडर को राज्य स्तर पर आई–सक्षम की टीम के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें खेल–खेल के माध्यम से पढ़ाने की शैली बताई गयी। जमुई सदर और खैरा प्रखंड से कुल 13 एडू लीडर का चयन किया गया, जिनके नाम जूही, चांदनी, शिल्पा, करिश्मा, रूपा, ज्योति, रूपम रवीना, श्वेता, पुजा, प्रेमलता, अंशु, रीना गुप्ता है। चयनित एडू लीडर को सप्ताह में पांच दिन ढाई घंटे पढ़ाना होता था। साथ ही सप्ताह में एक बार इन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे इनका बेहतर तरीके से क्षमतावर्धन किया जा सके। मानदेय के रूप में प्रत्येक एडू लीडर को 15 सौ रुपये मिलते थे, जो उन्हें सम्बंधित संकुल स्तरीय

संघ स्वाभिमान और मुस्कान के द्वारा भुगतान किया गया। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, सामुदायिक केंद्र या फिर दीदी के घर का चयन किया गया, जहाँ पर एक ही कक्षा में विभिन्न वर्गों के बच्चे उपस्थित होते हैं। जमुई सदर में ताजपुर, लोहड़ा, दौलपुर, बालाडीह, चौडीहा में सेंटर की शुरुआत की गयी, वहीं खैरा में भी चार सेंटर नौडीहा, सिंगारीताड़ रायपुरा के स्कूलों में बनाया गया है। प्रत्येक सेंटर पर 30–40 बच्चे पढ़ने आते हैं। पहले फेज में इन दस सेंटरों पर कुल 600 बच्चों को शिक्षित किया गया। जीविका के प्रबंधकों एवं बीपीएम के द्वारा समय–समय पर इन केन्द्रों की निगरानी की जाती है। कोरोना काल में ग्रुप कॉल/कांफ्रेंस कॉल के माध्यम से बच्चों को शिक्षण गतिविधियों से जोड़ा गया। महीने में एक बार अभिभावकों से मिलकर उनके सुझाव लिए गए। एडू लीडर शिल्पा, करिश्मा, जूही और रूपा ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। चौडीहा की रहने वाली करिश्मा बताती हैं कि पहले उसे अपनी बात को रखने में घबराहट होती थी, लेकिन आई–सक्षम से जुड़ने के बाद उसे इससे निजात मिल गयी है। वहीं दौलतपुरा गाँव की शिल्पा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि– 'जब उसने बतौर एडू लीडर के तौर पर काम करना शुरू किया तो शुरुआत में काफी चुनौतियां आईं। एक ही कक्षा में विभिन्न वर्गों के बच्चों को संतुलित एवं अनुशासन में रखकर शिक्षा प्रदान करना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन यह सब जीविका और आई–सक्षम की संयुक्त पहल से संभव हो सका है।' शिल्पा की माँ रानी देवी राधाकृष्ण जीविका स्वयं समूह की सदस्य है। आज शिल्पा आई सक्षम से जुड़ने के साथ–साथ अर्थशास्त्र से स्नातक भी कर रही है। जूही और रूपा आज इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि वे अपने समाज में लड़कियों एवं महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता पर काम कर रही हैं।

केस–4 **सकारात्मक बदलाव**

बाल विवाह के खिलाफ दीदियाँ हो रहीं मुखर

सुपौल जिला में पिपरा प्रखंड स्थित नंदनी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुदामा दीदी ने बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज मुखर कर एक बच्ची का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया।

एक दिन सुदामा अपने समूह की बैठक में भाग लेने पहुंची तब उन्हें पता चला कि समूह सदस्य सविता दीदी की बेटी रिंकु की शादी की तैयारी हो रही है। रिंकु की उम्र महज 16–17 वर्ष थी। वह 10वीं की पढ़ाई पूरी कर आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कर देना चाहते थे। इससे रिंकु की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती। रिंकु के विरोध के बावजूद उसकी शादी की जा रही थी। सुदामा देवी ने सविता दीदी से बात की और बेटी की शादी रोकने का आग्रह किया। लेकिन सविता दीदी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लिहाजा सुदामा दीदी ने इस बात की चर्चा ग्राम संगठन की बैठक में की। चूंकि रिंकु की उम्र अभी शादी के लायक नहीं थी ऐसे में ग्राम संगठन की दीदियों ने एकमत होकर उसका विवाह रोकने का फैसला किया।

ग्राम संगठन की अन्य दीदियों का साथ लेकर सुदामा देवी रिंकु के घर पहुंची और उसके पिता से बात की। उसने रिंकु के माता–पिता से कहा कि कम उम्र में बेटी की शादी करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। अभी उसकी उम्र पढ़ने की है। पढ़–लिखकर वह अपना भविष्य संवार सकती है। साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र में बेटी की शादी करना कानूनन अपराध भी है। दीदियों के काफी समझाने के बाद रिंकु के माता–पिता उसकी शादी दो साल तक टालने पर सहमत हो गए। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वर पक्ष ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। वर पक्ष ने कहा कि उन्होंने शादी समारोह आयोजित करने

के लिए काफी पैसे खर्च कर दिए हैं। उस खर्च की भरपाई होनी चाहिए। इसके बाद फिर से ग्राम संगठन की दीदियों ने लड़के के परिवार से बात की। दीदियों ने कहा कि अगर शादी का दबाव डाला गया तो इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। यह सुन वर पक्ष के भी होश ठिकाने आ गए और फिर वे भी शादी दो साल तक टालने पर सहमत हो गए। रिंकु इन्टर की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और अब वह ब्यूटी पार्लर का काम भी सीख रही है ताकि शादी के बाद वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। रिंकु का कहना है कि शादी के पूर्व जिम्मेदारियां कम रहती है, ऐसे में वह अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है।

ग्राम संगठन की दीदियां बाल–विवाह से होने वाले खतरों को लेकर जागरूक एवं सतर्क है। यही कारण है कि वे अपने आस–पास होने वाले बाल विवाह के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती हैं। ग्राम संगठन विभिन्न माध्यमों से लगातार दीदियों को बाल–विवाह न करने के लिए जागरूक एवं प्रेरित कर रही हैं।

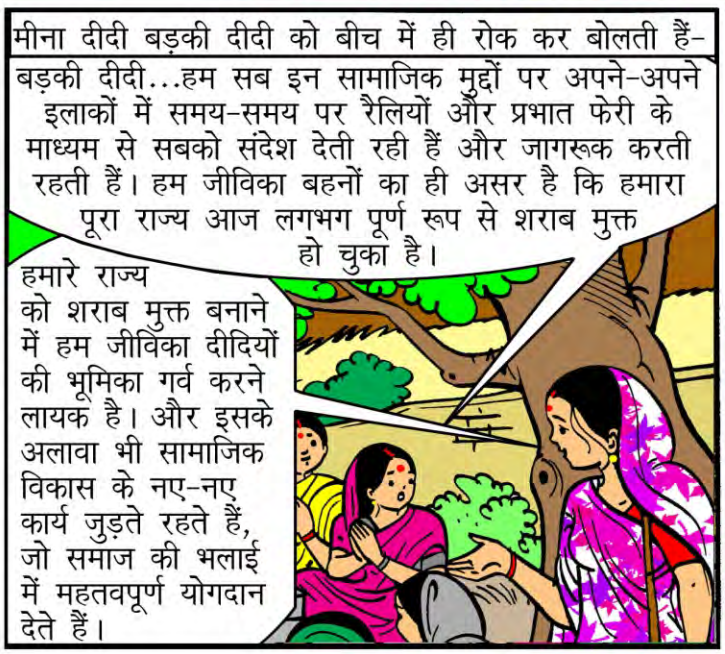

बड़की दीदी
बड़की दीदी घर जाते हुए एक ग्राम संगठन की बैठक के पास से गुजरती है।
मैं जीविका परियोजना की ओर से आयोजित सामाजिक विकास की कार्यशाला से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर लौटी हूँ। कल ग्राम संगठन की एक विशेष बैठक बुलाओ। मैं जरूरी मुद्दों और उनसे सम्बंधित गतिविधियों पर चर्चा करूँगी।
बहुत अच्छा बड़की दीदी।
बैठक VO
दूसरे दिन ग्राम संगठन की विशेष बैठक में बड़की दीदी आईं। सबने एक-दूसरे का अभिवादन किया।
हमारी परियोजना का एक विशेष विभाग है ''सामाजिक विकास ''जिसके अंतर्गत आप सब कई गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, है ना!
हाँ-हाँ बड़की दीदी... सामाजिक विकास की ओर से FSF और HRF का लाभ तो सभी को मिल ही रहा है, क्यूँ बहनो?
हाँ-हाँ दीदी... हम सबको उसका लाभ मिल रहा है।
बहुत बढ़िया बहनों, लेकिन ये तो सिर्फ एक अंग है सामाजिक विकास का। हमारी परियोजना के इस विभाग के अंतर्गत कई कार्य जुड़े हैं, जो समाज के प्रति हमें जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का मौका देता है। किसी भी समाज को स्वास्थ और बेहतर बनाने हेतु यह जरूरी है कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जाए जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, शराब एवं नशाखोरी पर प्रतिबंध...
मीना दीदी बड़की दीदी को बीच में ही रोक कर बोलती हैं-
बड़की दीदी...हम सब इन सामाजिक मुद्दों पर अपने-अपने इलाकों में समय-समय पर रैलियों और प्रभात फेरी के माध्यम से सबको संदेश देती रही हैं और जागरूक करती रहती हैं। हम जीविका बहनों का ही असर है कि हमारा पूरा राज्य आज लगभग पूर्ण रूप से शराब मुक्त हो चुका है।
हमारे राज्य को शराब मुक्त बनाने में हम जीविका दीदियों की भूमिका गर्व करने लायक है। और इसके अलावा भी सामाजिक विकास के नए-नए कार्य जुड़ते रहते हैं, जो समाज की भलाई में महतवपूर्ण योगदान देते हैं।
तो सुनो बहनों, मैं एक-एक करके बताती हूँ! अभी कुछ दिनों से वन विभाग के साथ मिलकर हमारी परियोजना से जुड़ी बहनों को ''दीदी की पौधशाला'' नाम के कर्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दीदियों को उनकी जमीन पर भिन्न-भिन्न फलदार और छायादार पौधों को उगाने का मौका मिलता है और फिर वन विभाग उचित मूल्य पर उनसे वो पौधे खरीद लेता है। इस कार्यक्रम के तहत एक ओर जहां हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे उपलब्ध होते हैं, वहीं दूसरी ओर दीदियों को आजीविका का एक साधन भी उपलब्ध हो रहा है।
अरे वाह बड़की दीदी, यह तो बड़ी अच्छी बात है!

और सभी जिलों में सौर ऊर्जा से संचालित सोलर लाईट और एल.ई.डी. बल्ब बनाने के संस्थान चलाए जा रहे हैं, जिससे जुड़ कर हमारी परियोजना की दीदियों को रोजगार मिल रहा है और न्यूनतम मूल्यों पर बाजार में सोलर उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

आजीविका का एक और आयाम है, हमारी परियोजना के सामाजिक विकास के अंतर्गत!

तो बताइए ना दीदी, और क्या-क्या है इसमें?

तुम सबने मनरेगा का नाम तो सुना ही होगा। तो सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के अंतर्गत जीविका से जुड़ी दीदियों और उनके परिवार के योग्य सदस्यों को मनरेगा की ओर से पौधारोपण, तालाब के निर्माण, सड़क निर्माण के कार्यों के साथ-साथ बकरी तथा मुर्गी पालन के कार्यों से ग्रामीणों को जोड़ने में उनकी सहायता कर उन्हें अपना जीवनयापन करने का मौका देती है हमारी परियोजना।

और सुनो बहनो, अभी कुछ महीने पहले ही हमारी परियोजना में एक नया कार्यक्रम जुड़ा है जिसे VPRP का नाम दिया गया है।

हमारे गाँवों में ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ अथवा कार्य किए जाते हैं। लेकिन कभी-कभी लोगों तक कुछ योजनाओं का लाभ पहुँच नहीं पाता है। इसके लिए सर्वे करके वहाँ के लोगों को मिलने वाली मौलिक सुविधाओं की कमियों की सूची बनाकर सम्बंधित विभागों को दी जाती है, ताकि समाज के सर्वांगीण विकास को और भी बल मिले।

बड़की दीदी, इसमें कौन-कौन-सी सुविधाओं की सूची बनायी जाती है?

शिक्षा के क्षेत्र में भी सामाजिक विकास की ओर से कई बेहतरीन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दसवीं तक के बच्चों के लिए 'प्रथम' नाम से जाने-माने अनुभवी शिक्षकों द्वारा मोबाइल पर ऑनलाइन कक्षाएँ चलायी जाती हैं और 'टर्न द बस' के नाम से 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अपनी-अपनी परीक्षाओं में टॉप करनेवाले छात्रों एवं विशेष शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का निःशुल्क लाभ दिया जा रहा है। तुम सब अपने घर के तथा आस-पास के बच्चों को इसका लाभ दिलवा सकती हो।

वाह बड़की दीदी, आज तो आपने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं हमें।

हाँ बहनो, और मुझे आशा है कि आज मैंने सामाजिक विकास हेतु किए जा रहे जिन कार्यक्रमों और जरूरी बातों की जानकारी दी है, तुम सब उससे जुड़ोगी और ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत बल्कि अपने पूरे समाज की भलाई के लिए आगे आओगी।

जरूर बड़की दीदी!

बैठक SHG

फिर अभिवादन कर बड़की दीदी चली जाती हैं।

संतोष कुमार, प्रबंध्क-संचार, नालंदा

मन की कलम से

"हम" से हमारा समाज

मैं से तुम से
मिलकर बने "हम"
हमसे बने हमारा समाज
समतामूलक समाज

न्याय हो, नेह हो
हो मानवता मानव में
आओ मिलकर भरे हुँकार
हो सुंदर हमारा समाज

लेकिन,
अब भी हैं
बहुत समस्याएँ इसमें
पुरातन से है घेरे बाधाएँ इसमें

मिलकर करना होगा जतन
न रहे कमजोर कोई तन–मन

आओ हो जाएँ एक
एक–एक कर बने अनेक
एकता से तोड़ेंगे बाधाएँ,
मिलकर खुशहाली का परचम लहराएँ

हो मुश्किल राह कितनी भी
विषम शूल सा पथ हो कितना भी
हाथ पकड़ बढ़ते जाएँ
प्रगति की सीढ़ी चढ़ते जाएँ

मैं बढूँगा, तुम बढ़ोगे
बढ़ेगा हमारा समाज

प्रकृति–पर्यावरण मानवता संग
आओ बनाएँ
सम – सुंदर – सम्यक हमारा समाज ।

Suman Kumar Jha
Manager Communication,
Kishanganj

रचना आमंत्रण

जीविका द्वारा **''चेंज मेकर्स''** (द्विभाषीय – त्रैमासिक) पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। पत्रिका में जीविका सम्पादित गतिविधियों / कार्यक्रमों / सफलता की कहानियों के प्रकाशन के साथ ही विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे जीविका कर्मियों के अनुभवों को भी स्थान दिया जाता है। जीविका कर्मियों से आग्रह है कि वे जीविका से जुड़े अपने अनुभवों /सफलता की कहानियों / कविता / गतिविधियों आदि को **''चेंज मेकर्स''** में प्रकाशन के लिए भेजें। रचना हिन्दी और अंग्रेजी या दोनों में से किसी भी भाषा में हो सकती है। रचना के साथ उससे संबंधित तस्वीरें अवश्य संलग्न हों। रचनाकार अपनी रचना के साथ अपना पूरा पता और संपर्क नंबर का उल्लेख अवश्य करें। रचना को निम्न मेल आईडी पर भेज सकते हैं –

changemakers.brlp@gmail.com

प्रकाशन योग्य रचनाओं को रचनाकार के नाम के साथ पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा।

– संपादकीय टीम, चेंज मेकर्स

Sustainable Development

Village to downtown
Path of development
With sustainable plan
Community is the key
In achieving prosperity
Mitigating the down.

Assertive efforts with
Social cohesion
Meets the requirement
For attaining the passion
to reach the culmination
Of development plan

Sitting together
Discussing the progression
To finalize the goal
Achieving more & more
Motivating themselves
To the bottom of the heart
For satisfying the social soul
Really fighting their rights
Development is prime Social choice

Anand Shankar
SPM-HRD

Celebrating Poshan Maah
across Bihar to ensure
Nutritious Food to Everyone

Independence day Tableau
Presentation
at Gandhi Maidan, Patna

Inauguration of Didi Ka Silai Ghar
(Stitching Unit)
at Koilwar, Bhojpur, Bihar

Bihar Saras 2022
at Gyan Bhawan, Patna
to Showcase and Sell
SHG Products across the Country

बिहार सरकार

JEEViKA

Rural Development Department,Govt. of Bihar
Vidyut Bhawan - II,1st & 3rd Floor, Bailey Road, Patna- 800 021;
PhoneNo / Fax: +91 - 612-2504980 / 60,
Website : www.brlps.in :: E-mail : info@brlps.in